भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3072

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

डीपीडीपी नियम, 2025

3072. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागरिकों की डेटा गोपनीयता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 में क्या विशिष्ट उपाय शामिल किए गए हैं;

(ख) डेटा न्यासधारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) डेटा संरक्षण विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी फर्मों और नागरिक समाज से प्राप्त फीडबैक सहित हितधारक के साथ परामर्शों का ब्यौरा क्या है और किस तरह से इन प्राप्त जानकारियों ने प्रारूप नियमों को आकार दिया है; और

(घ) इन नियमों को अंतिम रूप देने और लागू करने की समय-सीमा क्या है, और एक बार लागू होने के बाद उनकी प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ)**: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (अधिनियम) में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का इस तरह से प्रावधान किया गया है जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को चिह्नित करता है। यह अधिनियम मजबूत तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग में शामिल राज्य एजेंसियों सहित संगठनों को बाध्य करता है। डेटा फिड्यूशरीज़ की जवाबदेही की निगरानी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों के अधिनिर्णय के माध्यम से की जाती है और ऐसे उल्लंघनों के लिए दंड लगाया जाता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (नियम) के मसौदे में अधिनियम को संचालित करने का प्रयास

किया गया है। नियमों का उद्देश्य डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी द्वारा नोटिस प्रदान करने, उचित सुरक्षा सुरक्षा उपायों को लागू करने, व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना देने और डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के प्रयोग के लिए तंत्र प्रदान करने जैसे दायित्वों द्वारा नागरिकों की डेटा गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करना है। नियमों का मसौदा आदेशात्मक के बजाय सिद्धांत आधारित होने और डीपीडीपी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये नियम शिकायत निवारण तंत्र और डेटा उल्लंघनों के लिए रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियात्मक स्पष्टता प्रदान करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देशभर में डीपीडीपी नियम, 2025 के मसौदे पर कई सार्वजनिक परामर्श किए हैं। परामर्श में विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी फर्मों और सिविल सोसाइटी और प्रौद्योगिकी, परामर्श, एमएसएमई, बैंकिंग और वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कानून बनाने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप जनता और हितधारकों से फीडबैक/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस तरह के योगदान नियमों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करें । ये परामर्श सत्र डीपीडीपी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यावहारिक, नवाचार-अनुकूल नियामक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

******